डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 सितम्बर, 2021, डिस्पेच दिनांक 16 सितम्बर, 2021

| वर्ष 65 | अंक 8 | भोपाल | 16 सितम्बर, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

विकास का प्रकाश गरीबों तक पहुँचाने के लिए सरकार संकल्पित: मुख्यमंत्री श्री चौहान

पीएम स्वनिधि योजना के 50 हजार हितग्राहियों को 50 करोड़ की राशि वितरित की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। साथ ही जन-कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों का जीवन-स्तर बेहतर बनाया जा रहा है। विकास का प्रकाश गरीबों तक पहुँचाने के लिए सरकार संकल्पित है। हम गरीबों के समावेशी विकास तथा सबका साथ-सबका विकास की अवधारणा पर चल रहे है। प्रदेश में गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के साथ पढ़ाई-लिखाई और दवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान बालाघाट में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में प्रथम एवं द्वितीय किश्त वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 50 हजार हितग्राहियों के खाते में 50 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ भी किया। योजना के द्वितीय चरण में हितग्राहियों के खाते में ब्याज मुक्त 20-20 हजार रूपये की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह योजना कोविड संकट के दौरान प्रभावित होने वाले छोटे व्यापारियों के लिए संजीवनी बनी है। उन्होंने कहा कि स्वनिधि योजना से मिलने वाली सहायता राशि से छोटे व्यापारी धीरे-धीरे अपना काम बढ़ा सकते हैं। सरकार सबसे पीछे एवं सबसे नीचे के व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम हैं। योजना के प्रारंभ में ही लगभग 3.50 लाख हितग्राहियों को 10-10 हजार रूपये की सहायता राशि वितरित की गई थी। योजना के द्वितीय चरण के शुभारंभ पर प्रदेश के लगभग 1000 हितग्राहियों को योजना की द्वितीय किस्त 20-20 हजार रूपये प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ छोटे वर्ग को निरंतर मिल रहा है। इससे उनके जीवन की गाड़ी कोविड एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों में भी चल रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व-सहायता समूहों को कोविड संकट के पूर्व दी जाने वाली मदद को सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं में अद्भुत रचनात्मक शक्ति होती है। देश एवं प्रदेश का सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण अति आवश्यक है। गरीबों को अन्नोत्सव में कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्यान्न उपलब्धता से कोई पात्र गरीब वंचित न रहे। छूटे हुए नाम तत्काल जोड़ें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों का कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गरीबों के लिए रोटी के साथ मकान भी जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2024 तक सभी गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

गोदाम, ग्रेडिंग प्लांट्स का संचालन सुनिश्चित करे बीज संघ ● संचालक मंडल की बैठक में हुए महत्त्वपूर्ण निर्णय

बीज संघ की समितियों को प्रॉफिट मेकिंग बनाने कमेटी गठित

भोपाल। राज्य सहकारी बीज उत्पादक संघ की बीज उत्पादक समितियों को प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए समिति गठित की गई है। बीज उत्पादक समितियों को संचालित करने के लिये नई रणनीति बनाने और प्रॉफिट मेकिंग मॉडल तैयार करने के लिए एडवाइजरी कमेटी सुझाव देगी। संचालक मंडल के अध्यक्ष सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, संचालक मंडल के उपाध्यक्ष, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल की उपस्थिति में मंत्रालय में राज्य सहकारी बीज उत्पादक और विपणन संघ के संचालक मंडल की बैठक में समिति के गठन का निर्णय लिए गया । कृषि मंत्री श्री पटेल और सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने बीज उत्पादक समितियों को प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए एडवाइजरी कमेटी के गठन का निर्णय लिया । कमेटी में संचालक कृषि, एम डी अपेक्स बैंक, एम डी बीज प्रमाणीकरण संस्था एम डी बीज निगम, एमडी बीज संघ और बीज उत्पादन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले बीज उत्पादन समितियों के 3 सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। मंत्री श्री पटेल और मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि राज्य में हाइब्रिड और उन्नत किस्म के खरीफ और रबी सीजन की फसलों के बीजों की किसानों की मांग का आंकलन कर बीज उत्पादन करने की रणनीति तैयार की जाए। इससे राज्य के किसानों को रीजनेवल कीमत पर उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध होंगे। किसानों की माँग की आपूर्ति कर बीज उत्पादन समितियाँ भी घाटे से उबरने में सफल होंगी। प्रदेश में किसानों की बड़ी संख्या है, जिसे उन्नत किस्म के फसलों के बीज की आवश्यकता रहती है। **(शेष पृष्ठ 6 पर)**

प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों को अब तक रू. 109.89 करोड़ की राशि वितरित

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों और विदिशा जिले में बाढ़ प्रभावितों को सर्वोच्च प्राथमिकता से राहत राशि और अन्य सहायता प्रदान की गई है। संबंधित कलेक्टर्स सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही सहायता प्राप्त करने से वंचित न हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान वीडियो कॉंफ्रेंस द्वारा 9 जिलों के 24 हजार 529 हितग्राहियों को 31 करोड़ 51 लाख रूपये की राहत राशि का अंतरण किया। प्रदेश में अब तक एक लाख 27 हजार बाढ़ प्रभावित नागरिकों को 109 करोड़ 89 लाख रूपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह कार्यक्रम में मौजूद थे। राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत वर्चुअली शामिल हुए।

श्योपुर और अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों को ज्यों का त्यों बनाने का प्रयास, पुनर्निर्माण तेज करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गत दो माह संकट के रहे हैं। एक तरफ बाढ़ की स्थिति थी, वहीं दूसरी तरफ करीब डेढ़ दर्जन जिले कम बारिश से प्रभावित हुए हैं।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

जलवायु परिवर्तन सहित अन्य चुनौतियों से निपटने के प्रति सरकार है गंभीर- कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर

नई दिल्ली। किसानों की अथक मेहनत के दम पर आज कृषि निर्यात के मामले में भारत दुनिया में टॉप टेन में शामिल हुआ है। कोरोनाकाल में जब लगभग सभी उद्योग ठप्प हो गए थे तब भी देश के किसान काम कर रहे थे। किसानों ने कठिन समय में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है । यह बात केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के 16 वें सतत विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही ।

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि-"कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन सहित अन्य चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए भारत सरकार गंभीरता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। मौसम के असंतुलन से कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी विपरीत परिस्थितियों के मद्देनज़र सरकार पुरी तरह गंभीर है। हमारे वैज्ञानिक बहुत शिद्दत के साथ समुचित बीज आदि को लेकर काम कर रहे है।"

उन्होंने बताया कि - केन्द्र सरकार ने देश के छोटे और मझौले किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में लगभग एक लाख सत्तावन हजार करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं." प्रधानमंत्री ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम प्रारंभ की है, जो फूड प्रोसेसिंग सहित अन्य उद्योगों के लिए

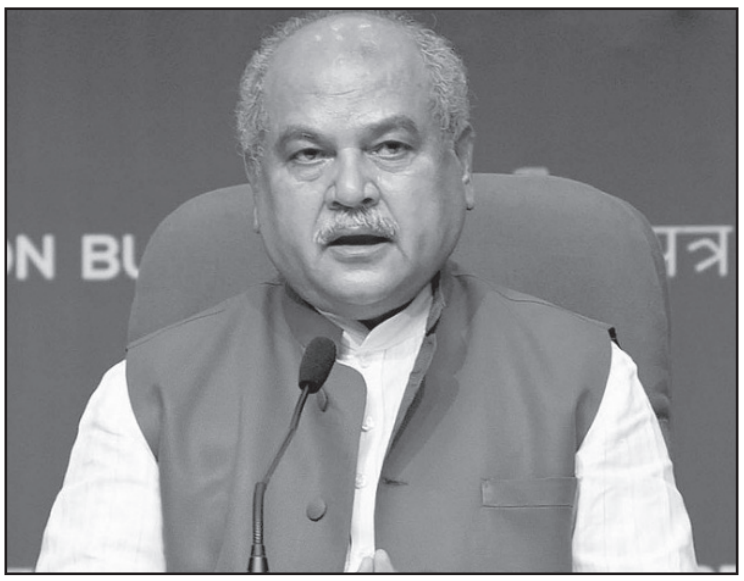

लाभदायक सिद्ध होगी।

किया जा रहा है खेतों के पास बुनियादी ढांचे का विकास

कृषि मंत्री ने बताया कि - छोटे व मझौले किसानों के लिए खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में सरकार के ठोस कदमों के तहत खेतों के पास बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। इस संबंध में एक लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया है, जिसके जरिये प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा रहे हैं। अब तक चार हजार करोड़ रूपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स मंजूर हो चुके हैं।

देश में 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन केंद्र की नई योजना के अंतर्गत किया जाएगा, जिसका काम प्रारंभ हो चुका है, जिससे किसानों को काफी सहायता मिलेगी, बेहतर बाजार मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी. किसानों के फायदे के लिए कृषि क्षेत्र को अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। देश में सत्तर से अधिक किसान रेल के साथ ही उड़ान योजना के माध्यम से भी किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

सम्मेलन को डेनमार्क की पर्यावरण मंत्री ली वर्मेलिन व सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी व एडवायजरी काउंसिल (सतत विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र) के चेयरमैन संजीव पुरी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कई उद्यमियों ने वर्चुअल रूप से सहभागिता की ।

नारियल के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी : नरेंद्र सिंह तोमर

नई दिल्ली। भारत ने नारियल उत्पादन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, भारत उत्पादन व उत्पादकता में सबसे आगे है व विश्व में तीसरे स्थान पर है । 2020-21 के दौरान देश में नारियल का उत्पादन 21207 मिलियन टन रहा, जो वैश्विक उत्पादन का 34 प्रतिशत है। उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 9687 टन है, जो विश्व में सर्वाधिक है। नारियल के नए उत्पाद बढ़ रहे है, जिससे किसानो को रोजगार मिल रहा है, यह प्रतिपादन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ने किया । एशिया व प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के तत्वावधान में स्थापित, नारियल उत्पादक देशो के अंतर शासकीय संगठन

इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी के स्थापना दिवस के स्मरणोत्सव में विश्व नारियल दिवस मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वे बोल रहे थे।

इस वर्ष 23वें विश्व नारियल दिवस समारोह के लिए विषय था 'कोविड-19 महामारी के बीच व उसके उपरांत सुरक्षित, समावेशी, सुदृढ़ और सुस्थिर नारियल समुदाय का विनिर्माण'.केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि हमारे किसान लघु व सीमांत श्रेणी के हैं, इसलिए देशीय नारियल उद्योग का भविष्य फार्म स्तर पर ही नारियल के उत्पादन का संचयन एवं एकत्रीकरण करने से तय होता है । किसानो की बेहतर आय प्राप्ति के लिए प्रसंस्करण व मूल्यवर्धन करने, उत्पाद विविधीकरण अपनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

देश के ग्रामीण अर्थ तंत्र को मिलेगी और मजबूती, पशुपालन-डेयरी मंत्रालय व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बढ़ाए कदम

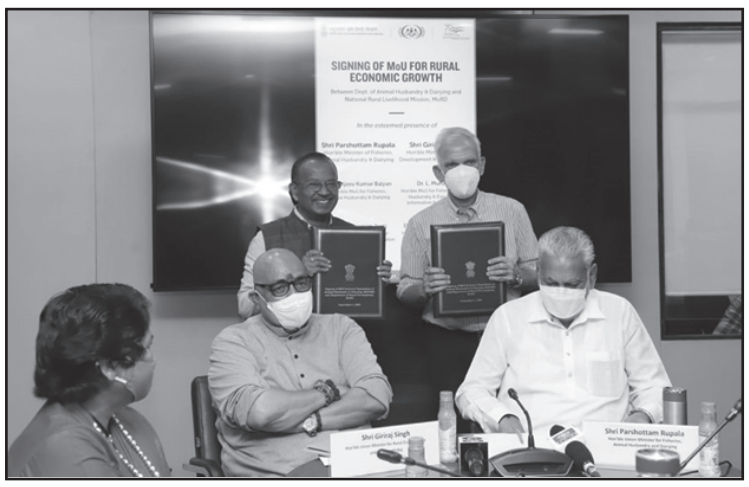

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में पशुपालन व डेयरी मंत्रालय का ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ ग्रामीण आर्थिक वृद्धि विषय को लेकर समझौता हुआ है। इस समझौते से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी ।

केंद्र सरकार देश के ग्रामीण अर्थ तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में पशुपालन डेयरी व ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच ग्रामीण आर्थिक वृद्धि विषय को लेकर एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। एमओयू के मसले पर बात करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह समझौता ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सार्थक शुरुआत है ।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, पशुधन संसाधन व्यक्तियों और प्राथमिक सेवा प्रदाताओं के उपयोग को सुनिश्चित करता है जिससे ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी मदद मिलेगी।

इस अवसर पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने केंद्र प्रेरित योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाकर ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। इस मॉडल को हेल्प कार्यकर्ता के रूप में आगे प्रशिक्षण और मान्यता प्रदान करके पशुधन के लिए डीएवाई एनआरएलएम के तहत विकसित मौजूदा कैडर का उपयोग करके पूरे देश में लागू किया जाएगा जो कि पशुपालकों को अन्य तरह की मदद देंगे ।

इस मिशन में 40 हजार से अधिक पशु सखियां हैं । यह पहल ग्रामीण भारत में इन सामुदायिक संवर्गों के माध्यम से डीएएचडी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा और इन संवर्गों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत तैयार कर उनकी आर्थिक तरक्की करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी बनेगा। ग्रामीण आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने से संबंधित जो समझौता हुआ है, उससे न केवल ग्रामीण आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी, बल्कि महिलाएं एवं पशुपालकों की स्वावलंबी बनाकर बनाकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरी करने की पहल भी होगी ।

देश में बड़े स्तर पर होगी जड़ी-बूटियों की खेती, सरकार ने शुरू किया अभियान, बांटे जाएंगे 75 हजार औषधीय पौधे

नई दिल्ली। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMBP) द्वारा शुरू किए गए अभियान के अंतर्गत देशभर में 75 हजार हेक्टेयर रकबे मे औषधीय पौधों की खेती की जाएगी । मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एनएमपीबी ने देशभर में जड़ी-बूटियों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरूआत की है । "इस कदम से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और हरित भारत का सपना पूरा होगा। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और महाराष्ट्र के पुणे से की गई है।

किसानों को बांटे गए औषधीय पौधे

पुणे में औषधीय पौधे किसानों को बांटे गए हैं और जो लोग पहले से जड़ी-बूटियों की खेती कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया गया । महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पारनेर से विधायक नीलेश लंके, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) के महानिदेशक डॉ. आसिम अली खान और एनएमपीबी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.

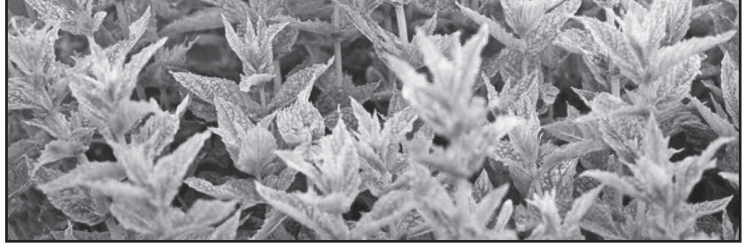

चंद्रशेखर सांवल ने अलग-अलग स्थानों से कार्यक्रमों की अगुवाई की।

75 हजार पौधे वितरित करने का लक्ष्य

सांवल ने कहा, "इस प्रयास से देश में औषधीय पौधों की आपूर्ति में और तेजी आएगी." इस अवसर पर 75 किसानों को कुल मिलाकर 7500 औषधीय पौधे वितरित किए गए। इसके अलावा 75 हजार पौधे वितरित करने का लक्ष्य भी तय किया गया। बयान के मुताबिक, सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉ. धर्म सिंह सैनी, एनएमपीबी के अनुसंधान अधिकारी सुनील दत्त और आयुष मंत्रालय के अधिकारियों ने संबंधित कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

अश्वगंधा की बढ़ी है मांग

इस मौके पर सैनी ने जड़ी-बूटियों की खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया. आसपास के कई जिलों से आए 150 किसानों को औषधीय पौधे नि:शुल्क वितरित किए गए । पिछले डेढ़ वर्षों में न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में औषधीय पौधों की मांग में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी देखने में आई है.। यही कारण है कि अमेरिका में अश्वगंधा तीसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद बन गया है। पौधों की पांच प्रजातियां वितरित की गईं, जिनमें पारिजात, बेल, नीम, अश्वगंधा और जामुन के पौधे शामिल थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फसलों के एम.एस.पी. में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभार

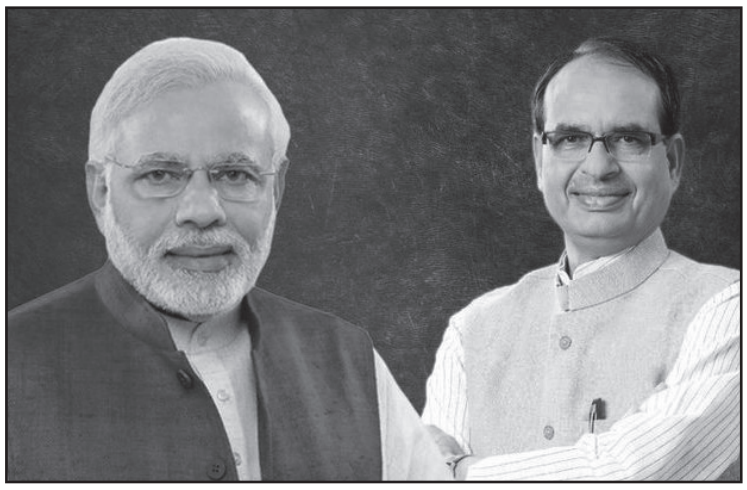

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार माना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसान हितैषी प्रधानमंत्री हैं। वे किसानों के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गेहूँ, जौ, चना, मसूर, कुसुम के फूल और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

प्रति क्विंटल वृद्धि

- गेहूँ - 40 रूपये
- चना - 130 रूपये
- जौ - 35 रूपये
- मसूर - 400 रूपये
- सरसों - 400 रूपये
- कुसुम के फूल - 114 रूपये

प्रदेश के बासमती को जीआई टैग से लाखों किसानों को होगा लाभ : कृषि मंत्री श्री पटेल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना होगा साकार

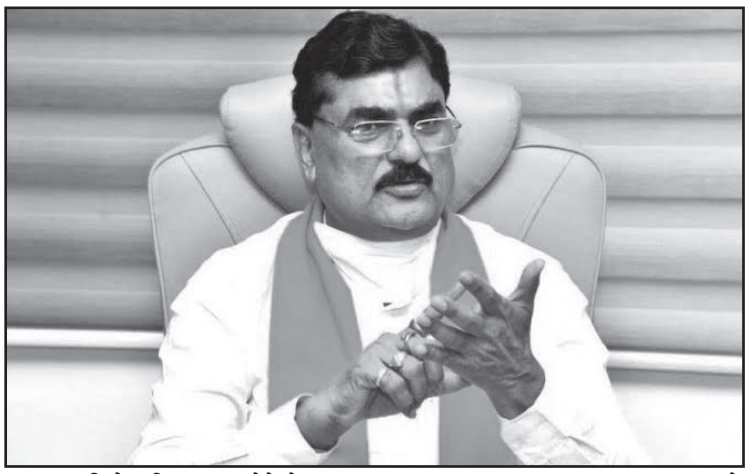

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि बासमती धान के जीआई टैग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिली है। इससे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की किसानों की आय बढ़ाने का सपना भी पूरा होगा। श्री पटेल ने इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किये गये प्रयासों के लिये प्रदेश के किसानों की ओर से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि मध्यप्रदेश के 13 जिले मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर और नरसिंहपुर में लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में एक लाख किसानों द्वारा बासमती धान उगाई जा रही है। प्रदेश का बासमती विशेष किस्म का होने के साथ ही खूशबूदार भी है। प्रदेश के किसानों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मद्रास हाईकोर्ट को नये सिरे से विचार करने के निर्देश देने के फैसले से राहत मिली है। इससे प्रदेश के धान उत्पादक किसान उत्साहित है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 अक्टूबर, 2020 को दी गई मध्यप्रदेश के किसानों के हित में अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि इस राहत से प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। इससे किसानों की आय तीन गुनी बढ़ जायेगी।

म.प्र. में कृषि क्षेत्र में नयी योजनाओं पर अमल के साथ नवाचारों को बढ़ावा

भोपाल। कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था वाला मध्यप्रदेश कृषकों को सक्षम और सम्पन्न बनाने के लिए कृत-संकल्पित है। राज्य सरकार ने लगातार कृषि कल्याणकारी योजनाओं और नवाचारों को बढ़ावा दिया है। किसान हित में ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं।

गेहूँ उपार्जन में अग्रणी

गेहूँ उपार्जन में प्रदेश अब अग्रणी राज्य है। किसानों के हित में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करते हुए ई-ट्रेडिंग का प्रावधान और किसानों को उपार्जन केन्द्र के साथ ही मंडी के अधिकृत निजी खरीदी केन्द्र और सौदा-पत्रक व्यवस्था से भी फसल बेचने की सुविधा प्रदान की गई।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश भी

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में ट्रायल के तौर पर जिन 6 राज्यों का चयन किया गया है, उसमें मध्यप्रदेश भी है। प्रदेश के किसान इस योजना से अधिक से अधिक लाभान्वित हो, इसके लिए राज्य सरकार समन्वय और प्रशासनिक सुदृढ़ता से काम कर रही है। योजना से लाभान्वित प्रथम हितग्राही श्री रामभरोस विश्वकर्मा प्रदेश के हरदा जिले का निवासी है।

कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में अग्रणी म.प्र.

कृषि अवसंरचना कोष के लिए प्रदेश को 2020-21 में 7500 करोड़ रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके उपयोग में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस कोष के जरिये आधुनिक मंडियों की स्थापना, फूड पार्क, शीत गृहों की श्रृंखला स्थापित करने के साथ साइलोस एवं वेयर हाउस के निर्माण को मिशन मोड में प्रोत्सातहित किया जा रहा है। इससे किसान अपनी उपज को एम.एस.पी. के स्थान पर एम.आर.पी. पर बेचने हेतु सक्षम होंगे।

नेशनल एग्रीकल्चर इन्फ्रा फायनेंसिंग फेसिलिटी पोर्टल

नेशनल एग्रीकल्चर इन्फ्रा फायनेंसिंग फेसिलिटी (एआईएफ़) पोर्टल पर बहुत ही कम समय में 2,352 आवेदन आये हैं। इनका लगातार सत्यापन किया जा रहा है और 618 करोड़ का भुगतान भी बैंकों द्वारा कर दिया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारिक तंत्र को मज़बूत करना है, जिससे देश के बड़े बाज़ारों तक किसानों की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

10 हजार रूपये सालाना सम्मान निधि

प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष 6-6 हजार रूपये तो मिल ही रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री किसान-कल्याण सम्मान निधि योजना की शुरूआत कर किसानों को मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रतिवर्ष 4 हजार रूपये दो बराबर किश्तों में दिये जा रहे है। इस प्रकार किसानों को अब कुल 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि मिल रही है।

सिंचाई क्षमता में वृद्धि को प्राथमिकता

किसानों की आय को बढ़ाने के लिये बेहतर प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं पर भी प्राथमिकता से कार्य करवाये जा रहे हैं। प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

अब डिजिटल कृषि भी

मध्यप्रदेश में डिजिटल एग्रीकल्चर अंतर्गत लगातार काम किया जा रहा है। खेती को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से लाभदायक और टिकाऊ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का इस्तेमाल ही डिजिटल एग्रीकल्चर है।

इस तरह कृषि क्षेत्र में बेहतर योजनाओं, रणनीति, प्रशिक्षण, संवाद और सहभागिता सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के प्रयासों का ही सुफल है कि प्रदेश के किसान आत्म-निर्भर और अग्रणी बनकर आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

ग्रामीण युवाओं को मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण

करीब 50 हजार लोगों को स्थानीय स्तर पर मिलेंगे रोजगार के अवसर

भोपाल। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक गाँव में पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति के लिये नलजल प्रदाय योजनाएँ बनाने का कार्य किया जा रहा है। इन नलजल योजनाओं का संचालन-संधारण ग्राम स्तर पर समुदाय की भागीदारी के साथ ग्राम/ग्राम पंचायत के अंतर्गत गठित की गयी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा। संधारण कार्यों के लिए स्थानीय ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की अवधारणा में तकनीकी दक्षता में प्रशिक्षण उपरांत तैयार कुशल मानव संसाधन को रोजगार के पर्याप्त एवं बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्रकार की गतिविधियों से जल आपूर्ति प्रणालियों का दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्यित करते हुए समुदायों के बीच जिम्मेदारी और उत्तरदायी नेतृत्व विकसित करने में मदद मिलेगी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा तकनीकी कौशल प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक ग्राम से चयनित किये गये उपयुक्त व्यक्तियों को मोटरपंप-रिपेयरिंग, प्लम्बर, पम्प-ऑपरेटर, मेसन (राज मिस्त्री), फिटर एवं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में लगभग 50 हजार व्यक्तियों को मध्यप्रदेश राज्य कौशल एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) के माध्यम से ऑफलाइन प्रशिक्षण दिलाये जाने का प्रस्ताव निष्पादित किया गया है। प्रशिक्षण व्यय जल जीवन मिशन के अंतर्गत "सपोर्ट एक्टिविटी मद" में भारित किया जायेगा, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 होगा। इस योजना की लागत 17.12 करोड़ रूपये है। प्रत्येक प्रशिक्षण-सत्र की अवधि तीन दिवस होगी। प्रशिक्षण-सत्र के उपरांत चौथे दिवस में प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा उन्हें प्रमाण-पत्र वितरित किये जायेंगे।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक गाँव में हर घर को नल से जल की सुविधा देने का कार्य किया जा रहा है, जो 2023 तक पूरा किया जाना है। प्रत्येक गाँव में पेयजल आधारित अधोसंरचना का निर्माण करने तथा नल योजना पूर्ण होने के बाद उसके रखरखाव एवं मरम्मत कार्य की सुविधा होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन/तकनीशियन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्थानीय मानव संसाधन को प्रशिक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उचित मूल्य दुकानों हेतु ऑनलाईन आवेदन 17 से 30 सितम्बर 2021 तक

दमोह। दमोह जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु पात्र संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। उचित मूल्य दुकानों के नाम उक्तानुसार है, इनमें जनपद पंचायत दमोह में ग्राम पंचायत सलैया हटरी शामिल हैं।

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश अभियान में बड़वानी में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन पर किसानों की कार्यशाला

भोपाल। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश अभियान के तहत बड़वानी में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन पर किसानों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने भी किसानों को आनलाईन वेबीनार के माध्यम से संबोधित किया। विभिन्न उद्यानिकी विशेषज्ञों ने वर्चुअल तरीके से उपस्थित किसानों को आय दोगुनी करने के लिए उन्नत तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किसानों के प्रश्नो-जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यशाला में एक जिला-एक उत्पाद में चयनित अदरक उत्पादन के लिए किये जाने वाले प्रयासों एवं विभिन्न प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए मिलने वाले अनुदानों के बारे में विस्तार से बताया।

वेबिनार के माध्यम से इन लोगों ने किया संबोधित

बड़वानी के जलसा रिसोर्ट में आयोजित संगोष्ठी को वेबिनार के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि राज्य शासन का प्रयास है कि किसानों की आय दोगुनी हो। इसके लिए एक जिला-एक उत्पाद में स्थानीय स्तर पर उत्पादित फसलों को बढ़ावा देने एवं उससे संबंधित प्रोसेस यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है। बड़वानी जिले के लिए अदरक का चयन किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित वेबिनार कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि अदरक के क्षेत्र में बड़वानी जिला नये कीर्तिमान स्थापित करेगा।

वेबिनार में ग्लोबल फूड के सीईओ श्री रामनाथ सूर्यवंशी ने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शासन ने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएँ बनाई हे। इन योजनाओं का लाभ लेते हुए किसान बंधु अपना एवं अपने क्षेत्र का विकास कर सकते है। किसानों को योजना का लाभ लेने में कोई दिक्कत हो तो संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन से निराकरण करवा सकते है।

योजनाओं में किसानों को दिये स्वीकृति पत्र

आयोजित कृषक संगोष्ठी में 15 किसानों को उद्यानिकी विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति पत्र वितरित किये। किसानों को प्याज भण्डारगृह, मिर्च फसल, ड्रिप सिंचाई, पैक हाउस और लो-एनर्जी कूल चैंबर योजना के स्वीकृति पत्र दिये गये।

लगाई गई प्रदर्शनी

संगोष्ठी स्थल पर ही किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी देने देश की अग्रणी कंपनियों के द्वारा अपने स्टाल लगाकर विभिन्न संयंत्र एवं जैविक खाद, दवाई, प्रदर्शित की गई। विभिन्न शासकीय विभागों ने भी अपने स्टाल के माध्यम से किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

बाँस के समग्र विकास का 5 वर्षीय रोड-मेप तैयार

देवास और हरदा जिले के 3800 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा बाँस रोपण

भोपाल। प्रदेश में एक जिला-एक उत्पाद योजना में देवास और हरदा जिले में बाँस क्षेत्र के समग्र विकास का 5 वर्षीय रोड मेप तैयार किया गया है। इन दोनों जिले में 3800 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस रोपण के साथ 2500 किसान और बाँस शिल्पियों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

वन विभाग के अधीन राज्य बाँस मिशन द्वारा इन जिलों में बाँस प्र-संस्करण की 6 इकाइयाँ भी स्थापित की जाकर बाँस विपणन में सहयोग प्रदान करेगा। बाँस मिशन देवास और हरदा जिले के किसानों को प्रोत्साहित कर 1400 हेक्टेयर अनुपजाऊ निजी भूमि पर बाँस रोपण कराकर अनुदान उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा विभागीय रोपण और मनरेगा में 2250 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस-रोपण करायेगा।

बाँस मिशन की इस महत्वाकांक्षी योजना में किसानों और बाँस शिल्पियों को तकनीकी मार्गदर्शन और कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाकर किसानों और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

इसी तरह प्राथमिक प्र-संस्करण और मूल्य वर्धन इकाइयों की स्थापना के साथ ही बाँस कटाई के बाद के बुनियादी ढ़ाँचे का विकास किया जा सकेगा। बाँस उत्पादों को बेहतर कीमत दिलाने के लिए बाँस बाजार और एम्पोरियम का सहयोग लिया जाएगा।

लघु वनोपज संग्रहण के लिए 6 जिलों के लिए बना एक्शन प्लान

भोपाल। वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया कि प्रदेश में 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना में लघु वनोपज संग्रहण के लिए 6 जिलों के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। इसमें अलीराजपुर, सिंगरौली, उमरिया, बैतूल, मण्डला और अनूपपुर जिले शामिल हैं।

वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि अलीराजपुर में महुआ फूल और सफेद मूसली की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने से विशेष प्रयास कर विपणन और प्र-संस्करण के लिए 2 वन धन केन्द्र में मशीन स्थापित की जायेंगी। सिंगरौली जिले में महुआ फूल के प्र-संस्करण में 7 वन धन केन्द्रों का उपयोग किया जायेगा। उमरिया जिला में महुआ फूलों के प्र-संस्करण एवं विपणन के लिए स्थापित 6 वन धन केन्द्र के जरिए महुआ लड्डू, बिस्किट और केक बनाने के साथ महुआ बीज से तेल निकालने की योजना तैयार की गई है। स्थानीय वृक्षारोपण योजना में 6 स्थानों पर महुआ के पौधों का रोपण भी कराया गया है।

वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि बैतूल जिले में महुआ फूल और अचार गुठली के प्र-संस्करण एवं विपणन के लिए वन धन विकास केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसी तरह किसानों को भी निजी भूमि पर औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित कराया जाएगा। इन केन्द्रों पर तैयार उत्पाद स्थानीय बाजार, ट्राइफेड और संजीवनी केन्द्रों के माध्यम से विक्रय कराया जाएगा।

वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि मण्डला जिले में आंवला, अर्जुन छाल, शहद और महुआ के प्र-संस्करण की योजना तैयार की गई है। अनूपपुर जिले में गुलबकावली के संरक्षण एवं उत्पादन के लिए एक्शन प्लान के तहत पौधा-रोपण सहित विशेष प्रयास किये जायेंगे। इससे स्थानीय ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी।

बाँस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 30 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित

भोपाल : प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बाँस उद्योग स्थापित करने के लिए इस वर्ष 2 करोड़ 77 लाख 50 हजार रूपए का अनुदान प्रावधानित किया गया है। राज्य बाँस मिशन द्वारा निजी क्षेत्रों में इच्छुक हितग्राहियों से 30 सितंबर 2021 तक प्रस्ताव बुलाए गए हैं। बाँस उद्योग लगाने के लिए 10 कार्य क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। गत वित्तीय वर्ष में निजी क्षेत्रों के हितग्राहियों को 16 इकाईयों की मंजूरी दी जाकर 2 करोड़ 3 लाख रूपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया।

प्रमुख रूप से बाँस के ट्रीटमेंट तथा सीजनिंग प्लांट, बाँस प्र-संस्करण केन्द्र एवं मूल्य संवर्धन इकाई, बाँस कचरा प्रबंधन, अगरबत्ती इकाई, एक्टिवेटेड़ कार्बन प्रोडक्ट, बेम्बो बोर्ड/फ्लोर टाइल्स यूनिट और हाईटेक और बिग नर्सरी के प्रोजेक्ट पर अनुदान दिया जा सकेगा।

आधुनिक तकनीक का उपयोग कर अधिक आय प्राप्त करें किसान - मंत्री डॉ. मिश्रा

दतिया में 150 किसानों को दिये 10 लाख रुपये के कृषि यंत्र

भोपाल। प्रदेश सरकार पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के अनुरूप समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिये संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा वृंदावन धाम दतिया में आयोजित कृषि यंत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषकों को आधुनिक एवं उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिये, जिससे कि उन्हें अधिकतम आय प्राप्त हो सके। समारोह में अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के 150 किसानों को 10 लाख रुपये की राशि के कृषि यंत्र वितरित किये गये।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सलाह से अधिकतम आय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि परम्परागत कृषि के साथ ही उन्नत एवं आधुनिक तकनीक के संयोजन और नकदी फसलों की खेती से कृषक अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। कृषक वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार उन्नत तकनीकी, गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनायें। सफेद मूसली और अंजीर जैसी अधिक आय देने वाली फसलों को लगायें। कृषि के परम्परागत तरीकों में बदलाव लायें। दो फसलों के स्थान पर तीन फसल लेने का प्रयास करें। इससे किसानों को अधिकतम आय प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

वेटरनरी एवं फिशरीज कॉलेज का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करायें

मंत्री डॉ. मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि नौनेर में निर्माणाधीन वेटरनरी एवं फिशरीज कॉलेज का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आगामी शिक्षण सत्र से कॉलेजों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिये। कॉलेजों के प्रारंभ हो जाने से क्षेत्र को बहु-आयामी लाभ प्राप्त होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरविंद कुमार ने आश्वस्त किया कि हर हाल में जून-2022 से पूर्व निर्माण कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा, जिससे कि आगामी सत्र में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जा सके।

समारोह को कृषि वैज्ञानिकों के साथ ही पूर्व विधायक डॉ. आशाराम अहिरवार, श्री प्रशांत ढेंगुला और श्री गिन्नी राजा ने भी संबोधित किया। समारोह में डीन डॉ. सुनील कुमार चतुर्वेदी, डायरेक्टर श्री अनिल कुमार, श्रीमती रजनी पुष्पेन्द्र रावत, श्री रामजी खरे, श्री विपिन गोस्वामी सहित कृषक बंधु उपस्थित थे।

धान एवं ज्वार-बाजरे के उपार्जन के लिये पंजीयन प्रारंभ - श्री किदवई

भोपाल। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान एवं ज्वार-बाजरे के उपार्जन के लिये किसानों का पंजीयन 15 सितम्बर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया जायेगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये धान का न्यूनतम मूल्य 1940 रूपये, ज्वार 2738 रूपये एवं बाजरा 2250 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जिला स्तर पर होने वाला पंजीयन विगत रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी भू-अभिलेख के डाटाबेस के आधार पर किया जायेगा।

पंजीयन का सरलीकरण

श्री किदवई ने बताया कि किसानों को ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया गया है। किसान अब अपना पंजीयन डाटाएंट्री के अलावा एमपी किसान एप, प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं एवं विगत खरीफ वर्ष में उपार्जन/पंजीयन करने वाले महिला स्व-सहायता समूह एवं एफपीओ द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र से भी करा सकेंगे। इसके अलावा सिकमीदार एवं वनाधिकार पट्टाधारी अपना पंजीयन समिति/एफपीओ/महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित केन्द्रों में ही करा सकेंगे। प्रदेश में 1718 पंजीयन केन्द्र बनाए गए है।

पंजीयन के लिये दस्तावेज

प्रमुख सचिव खाद्य ने बताया कि पंजीकरण के लिये जिन किसानों ने खरीफ एवं रबी के मौसम में ई-उपार्जन

पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया था, उन्हें पुन: दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। किसान द्वारा विगत वर्ष दिये गये आधार कार्ड और बैंक पासबुक के आधार पर पंजीयन किया जा सकेगा। नये पंजीयन हेतु किसानों को यह दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वनाधिकार पट्टाधारी/सिकमीदार किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराना होगी। किसान से उपज के विक्रय के लिये 3 संभावित दिनांक प्राप्त की जायेंगी, जिसे पंजीयन के समय दर्ज किया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को भुगतान जेआईटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में किया जायेगा। अत: केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल खाते ही मान्य होंगे। किसान को बोई गई फसल की किस्म, रकबा तथा विक्रय योग्य मात्रा, फसल के भंडारण स्थान की जानकारी भी आवेदन में दर्ज कराना होगी।

सिकमी/बटाईदार किसान

सिकमी एवं बटाईदार श्रेणी के ऐसे किसान उपार्जन के लिये आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। ऐसे किसानों के अनुबंध की एक प्रति पंजीयन कराने वाले व्यक्ति/कृषक द्वारा संबंधित तहसीलदार को उपलब्ध कराना होगा। पंजीयन के समय सिकमी/बटाईदार के साथ मूल भू-स्वामी के आधार नम्बर की जानकारी भी ली जाएगी। पंजीयन के लिये 15 अगस्त 2021 तक कराये गये अनुबंध ही मान्य होंगे।

दावा-आपत्तियाँ एवं सत्यापन

किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि का रकबा एवं बोई गई फसल से संतुष्ट ने होने पर पंजीयन के पूर्व संशोधन हेतु गिरदावरी में दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति का निराकरण होने एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान की संशोधित जानकारी आने पर ही पंजीयन किया जा सकेगा। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के रकबा, फसल एवं किस्म का सत्यापन एसडीओ/नायब तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।

किसानों की सूची का प्रदर्शन

पंजीकृत किसानों की सूची रकबा एवं फसल की सूची कृषक के अवलोकन के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय एवं पंजीयन केन्द्र पर चस्पा की जायेगी। इसके अलावा एनआईसी द्वारा पंजीयन केन्द्र एवं DMMPSCSC लॉगइन पर, जनपद पंचायत एवं पंजीयन केन्द्रों, ग्राम पंचायत के कार्यालय एवं जिला उपार्जन नियंत्रक कक्ष के दूरभाष क्रमांक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

जल जीवन मिशन में 2521 करोड़ से अधिक के कार्य मंजूर

भोपाल। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की जल व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की कारगर पहल निरंतर जारी है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 2521 करोड़ 23 लाख 44 हजार रूपये लागत की जलप्रदाय योजनाओं की जल जीवन मिशन में मंजूरी दी है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की अब तक की सर्वाधिक 2840 जलसंरचनाएँ शामिल हैं।

अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग श्री मलय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश के 45 जिलों की ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं से जुड़े 2840 प्राप्त प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कर सक्षम अनुमोदन उपरांत स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पहलीबार इतनी बड़ी राशि की जलप्रदाय योजनाओं की एकजाई मंजूरी दी गई है। विभाग का मैदानी अमला यथाशीघ्र जलप्रदाय योजनाओं को पूरा कर ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा।

प्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए राष्ट्री य जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निरंतर जल -संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक करीब 3260 ग्रामों के शत-प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा चुकी है।

जल जीवन मिशन जल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों, सांसद आदर्श ग्रामों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल्य ग्रामों को प्राथमिकता में रखा जाता है। लोक स्वास्थ्यर यांत्रिकी विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष (31 मार्च 22) तक ग्रामीण आबादी को कुल 22 लाख 805 नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। विभाग द्वारा एकजाई 2840 जलप्रदाय योजनाओं की इस मंजूरी से आगामी माहों में विभाग की सुनियोजित और समयबद्ध कार्रबाई से शेष लक्ष्य को पूरा किया जायेगा।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति में भोपाल जिले की 31, रायसेन 53, सीहोर 17, विदिशा 37, राजगढ़ 37, होशंगाबाद 97, बैतूल 194, हरदा 44, धार 34, झाबुआ 14, खरगोन 148, बड़वानी 07, खण्डवा 57, उज्जैन 29, नीमच 03, शाजापुर 29, रतलाम 80, आगर मालवा 11, देवास 107, मंदसौर 64, ग्वालियर 28, अशोकनगर 19, शिवपुरी 39, दतिया 02, गुना 23, मुरैना 266, श्योपुर 27, भिण्ड 46, सागर 82, पन्ना 11, छतरपुर 57, टीकमगढ़ 06, जबलपुर 205, कटनी 57, मण्डला 90, बालाघाट 28, नरसिंहपुर 26, डिण्डौरी 51, छिन्दवाड़ा 207, सिवनी 183, रीवा 145, सतना 23, सीधी 55, शहडोल 40, तथा अनूपपुर जिले की 31 जल संरचनाएँ शामिल हैं। मिशन में नवीन जलप्रदाय योजनाओं के साथ ही विभिन्न ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नए सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत भी कार्य किये जायेंगे।

कृषि अनुसंधान और तकनीक के तालमेल से खेती को मिलेगी नई दिशा

जबलपुर । अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के मध्य कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन के मार्गदर्शन में एक अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ। जनेकृविवि के संचालक अनुसंधान सेवायें डॉ. जी.के. कोतू एवं एआईजीजीपीए के सीईओ श्री श्रीमन शुक्ला आईएएस ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किये। अनुबंध के तहत दोनों संस्थान परस्पर व्याख्यान, सेमीनार, कार्यशाला, पैनल के रूप में सहयोगी कार्यक्रम, वेबीनार, आदि क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करेंगे । इसके साथ ही संगठन में बुनियादी ढ़ांचे, संसाधानों और विशेषज्ञता की पारस्परिक साझेदारी भी करेंगे। दोनों संस्थानों में अधिकारियों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और छात्रों के ज्ञानार्जन के आदान-प्रदान हेतु लगातार सम्पर्क बना रहेगा ।

इस अनुबंध से नवीन अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हो सकेंगे। इस दौरान संचालक प्रक्षेत्र डॉ. दीप पहलवान, डॉ. एम.एस. भाले, आईपीआरओ डॉ. मुमताज अहमद खान एवं कृषि वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञगण शामिल रहे ।

(पृष्ठ 1 का शेष)

पीएम स्वनिधि योजना के 50 हजार....

गरीबों के विकास में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण में 5 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे।

हितालाभ वितरण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को मंच से हितलाभ वितरित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाल हृदय उपचार योजना के लिए चिन्हित हुए बच्चों को भी सहायता राशि के चेक प्रदान किये। जिले के 318 महिला स्व-सहायता समूहों को 4 करोड़ 26 लाख रुपए का क्रेडिट वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड़-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के लाभांवित व्यक्तियों से मुलाकात भी की।

योजनाओं के स्टालों का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में विभागों द्वारा योजनाओं की प्रदर्शनी के लिए लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने "एक जिला-एक उत्पाद" के तहत बालाघाट जिले से चिन्हित उत्पाद और बालाघाट में पैदा होने वाली विभिन्न प्रकार की धान की किस्मों की जानकारी भी ली।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह सागर से सजीव प्रसारण के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पूरे देश में सराहनीय कार्य कर रही है। सागर जिला पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है।

कार्यक्रम में खजुराहो सांसद श्री बी.डी. शर्मा एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा भी वर्चुअल शामिल हुए। श्री बी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन-कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इन योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आत्म-निर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। इस योजना के प्रथम चरण में हितग्राही को ब्याज मुक्त 10 हजार रुपए उपलब्ध कराये जाते है। हितग्राही द्वारा यह राशि जमा करने पर उन्हें सरकार द्वारा द्वितीय चरण में 20 हज़ार प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जल संसाधन विकास राज्य मंत्री एवं आयुष मंत्री श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, सांसद श्री ढाल सिंह बिसेन, विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, विधायक एवं अध्यक्ष खनिज विकास निगम प्रदीप जायसवाल सहित जन-प्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक एवं प्रदेश की सभी नगरीय निकाय इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल हुई।

मध्य प्रदेश में खरीफ का 145 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबा कवर

भोपाल । म.प्र. में खरीफ फसलों की बुवाई समाप्ति की ओर बढ़ रही है । अब तक 145 लाख 71 हजार हेक्टेयर रकबा कवर किया जा चुका है जो निर्धारित लक्ष्य 149 लाख 29 हजार हेक्टेयर के विरुद्ध लगभग 97.6 फीसदी है। गत वर्ष इस अवधि में 143.55 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। राज्य में धान और सोयाबीन की बुवाई 90 फीसदी से अधिक क्षेत्र में कर ली गई है। राज्य में अब तक कुल खाद्यान्न फसलें जिसमें अनाज और दलहन शामिल हैं उनका रकबा 76.35 लाख हेक्टेयर हो गया है जो गत वर्ष इस समय तक 71.69 लाख हेक्टे. था। वहीं राज्य के पांच संभागों में शत-प्रतिशत बोनी हो गई है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 118.50 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 145.71 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई है। इसमें राज्य की प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन की बोनी 55.84 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है। राज्य की दूसरी प्रमुख खरीफ फसल धान की बोनी अब तक 33.51 लाख हेक्टेयर में हुई है। इसी प्रकार प्रदेश में अब तक इन फसलों की बुवाई लक्ष्य से अधिक रकबे में कर ली गई है जिसमें मक्का 15.13 लाख हे. में, तुअर 4.25, उड़द 15.37, मूंगफली 3.79 एवं तिल 3.20 लाख हे. में तथा कपास की बुवाई 6.16 लाख हेक्टेयर शामिल है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक कुल अनाज फसलें 54.95 लाख हेक्टेयर में, दहलनी फसलें 21.39 लाख हेक्टे. में एवं तिलहनी फसलें 63.21 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। यदि संभागवार आंकड़ें देखें तो रीवा, सीधी, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग में लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत बुवाई कर ली गई है। वहीं लक्ष्य के विरुद्ध जबलपुर संभाग में 98.7 फीसदी, भोपाल संभाग में 97.8 फीसदी, नर्मदापुरम संभाग में 97.7 फीसदी, चंबल संभाग में 93.2 फीसदी एवं सागर संभाग में 86 फीसदी बुवाई कर ली गई है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों को .....

कोरोना का संकट भी रहा। हम नागरिकों और सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी थी। सरकार ने प्रयास किया कि हर परि स्थिति में जनता को संकट से निकालें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विशेष योजना बनाकर बाढ़ प्रभावितों को विभिन्न तरह की क्षति के लिए राशि प्रदान करने का कार्य किया गया है। लोगों को हुए नुकसान से जिंदगी की गाड़ी पटरी से न उतरे, इसके लिए पूरी तत्परता और पारदर्शिता से राहत राशि प्रदान की गई है। पंचायत भवन पर हितग्राही सूची चस्पां कर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राशि प्रदान करने के पूर्व हितग्राहियों के संबंध में दावे-आपत्ति का विकल्प भी दिया गया। कृषि फसलों की हानि के लिए अलग से राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत कार्यवाही हो रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राशि वितरण में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। विद्युत उप केन्द्रों और सड़कों आदि की बाढ़ से हुई क्षति के पश्चात पुनर्निर्माण के कार्यों को भी समय पर करना आवश्यक है। इसके लिए सभी कलेक्टर, जन-प्रतिनिधि, क्राइसिस मैनेजमेंट समूह के सदस्यों से परामर्श कर पूर्ण करें। नहरों की मरम्मत का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जाए।

हितग्राहियों को प्रदान की गई सहायता – एक नजर में

पूर्व में प्रदेश के एक लाख 2 हजार बाढ़ प्रभावितों को 78 करोड़ 38 लाख रूपये की राहत राशि दी गई थी। आज शहरी क्षेत्र के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए प्रति हितग्राही 2.50 लाख रूपए के मान से स्वीकृत प्रकरणों में प्रथम किश्त की राशि प्रति हितग्राही एक लाख रूपए प्रदान की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त भवनों एवं रेत, पत्थर आदि आ जाने अथवा मिट्टी कटाव से खेतों को पहुँची क्षति के लिए भी राहत राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज बाढ़ प्रभावित जिलों के नागरिकों को जो सहायता प्रदान की वह इस प्रकार है –

- नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 23 निकायों के 975 हितग्राहियों को 9 करोड़ 75 लाख रूपए की प्रथम किश्त की राशि।
- राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 592 बाढ़ प्रभावितों को 5 करोड़ 63 लाख रूपए की राशि।
- राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत जनहानि/पशुहानि/फसल क्षति में 23 हजार 554 बाढ़ प्रभावितों को 16 करोड़ 13 लाख करोड़ रूपए की राशि।

मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश

ग्वालियर और चंबल संभाग के जिन स्थानों पर बार-बार बाढ़ आती है, वहाँ यह विचार करें कि क्या ग्रामवासियों को उँचाई के स्थानों पर बसाया जा सकता है। इसके लिए अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जाए।

- कोई भी पात्र हितग्राही सहायता से वंचित न रहे।
- हितग्राहियों की सूची पंचायत भवन में प्रदर्शित की जाए।
- खेतों में हुई क्षति से संबंधित राहत प्रदान करने की प्रक्रिया भी पूर्ण की जाए।
- नहरों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए।
- कोरोना अनुकूल व्यवहार पर ध्यान देते हुए वैक्सीनेशन कार्य को गति दी जाए।

किसानों की शिकायतों का त्वरित गति से हो प्रभावी निराकरण – संभागायुक्त श्री कियावत

भोपाल । सभी जिला अधिकारी सी एम हेल्पलाइन में किसानों से संबंधित सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण करें। उक्ताशय के निर्देश संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने सी एम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के कृषि अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि बैंक या बीमा कंपनी की लापरवाही के कारण किसान का अटका हुआ फसल बीमा का क्लेम 7 दिन के अंदर किसान के खाते में जमा किया जाए। जिन शिकायतों का निराकरण हो चुका है, फिर भी लंबित हैं, उन्हें फोर्सक्लोज कराया जाए। सी एम हेल्पलाइन की सभी लंबित शिकायतों को विभाग के मैदानी अमले से समन्वय कर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जाए।

(पृष्ठ 1 का शेष)

बीज संघ की समितियों ...

बीज उत्पादक समितियों को इस दिशा में क्रियाशील करना होगा। इसके लिए नव-गठित एडवाइजरी कमेटी आवश्यक सुझाव देगी। एडवाइजरी कमेटी आंकलन करेगी कि प्रदेश में किसानों को किन-किन फसलों के कितनी मात्रा में बीजों की आवश्यकता होती है। राज्य के किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सर्टिफाइड उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज उत्पादन समितियों को कार्यशील किए जाने का मॉडल तैयार करेगी। कमेटी देश के ऐसे दूसरे राज्यों के बीज उत्पादन समितियों के सफल मॉडल का भी अध्ययन करेगी, जिनके द्वारा किसानों की माँग के अनुरूप उन्नत किस्म के बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

बैठक में चर्चा के दौरान यह विषय भी उठा कि प्रदेश में बीज उत्पादक समितियों द्वारा उत्पादित किए जा रहे बीज की सही सही जानकारी किसानों तक नहीं पहुँच रही है। बीज उत्पादक समितियों के द्वारा किस क्षेत्र में किस फसल का किस प्रजाति का बीज उत्पादित किया जा रहा है। बीज उत्पादक समितियों के पास कितनी मात्रा में बीज उपलब्ध है, आदि की जानकारी किसानों को मिलना चाहिए। किसानों द्वारा कौन-सी फसल के कौन-सी किस्म के बीजों की अधिक माँग है, इसकी जानकारी बीज उत्पादक समितियों को हो। इसके लिए बीज संघ के पोर्टल को क्रिस्प संस्था के माध्यम से शुरू करने के प्रस्ताव को संचालक मंडल द्वारा बैठक में स्वीकृति दी गई। बैठक में एसीएस कृषि एवं सहकारिता श्री अजीत केसरी, सहकारिता आयुक्त श्री नरेश पाल, एमडी अपेक्स बैंक और एमडी बीज संघ श्री पी.एस. तिवारी, संचालक कृषि सुश्री प्रीति मैथिल और अन्य सदस्य उपस्थित थे।

केसर किसानों से मिले कृषि मंत्री तोमर, हर संभव मदद का आश्वासन दिया

जम्मू-कश्मीर : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जम्मू-कश्मीर के पंपोर में इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड केसर स्पाइस पार्क का दौरा किया। तोमर के साथ कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी थीं। इस मौके पर तोमर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों के लिए हर संभव मदद और समर्थन देने के लिए तैयार है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केसर स्पाइस पार्क का दौरा

नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पंपोर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केसर स्पाइस पार्क के दौरे के दौरान उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक अहमद खान, प्रमुख सचिव-कृषि उत्पादन नवीन कुमार चौधरी, जिला विकास आयुक्त पुलवामा बसीर-उल-हक चौधरी भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में बोलते हुए तोमर ने कहा, "केंद्र सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। स्पाइस पार्क के अस्तित्व के साथ उत्पादकों की केसर उत्पादन से आय दोगुनी हो गई है। केंद्र सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। किसानों को सुविधाएं और सहायता प्रदान करना हमारी सरकार का लक्ष्य जो हमारे किसानों के जीवन को समृद्ध बनाएगी।"

महिला स्व-सहायता समूहों को 161 श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण विभाग अनुदान देगा – श्री भारत सिंह

स्व-सहायता समूहों की दीदियों के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह, समूहों की दीदियों को सौंपे 171 लाख की सहायता राशि के चैक

ग्वालियर। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भर भारत की नई इबारत लिख रहीं महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों को आर्थिक गतिविधियाँ आगे बढ़ाने के लिये धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। महिला स्व-सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उत्पादों की 161 श्रेणियों में आर्थिक अनुदान मुहैया कराया जाएगा। श्री कुशवाह शुक्रवार को ग्वालियर में मध्यप्रदेश-डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों की दीदियों के साथ संवाद कर रहे थे।

बाल भवन में आयोजित हुए संवाद कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह ने विभिन्न ग्रामों से आईं स्व-सहायता समूहों की दीदियों को आर्थिक गतिविधियाँ आगे बढ़ाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 171 लाख रूपए की आर्थिक सहायता के चैक भी सौंपे। जिनमें 17 समूहों की 53 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों के 23 लाख 60 हजार रूपए और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा क्रेडिट लिंकेज के रूप में दी गई 95 लाख व सेंट्रल बैंक द्वारा प्रदत्त 53 लाख रूपए की राशि शामिल है। कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री किशोर कान्याल तथा सर्वश्री कप्तान सिंह सहसारी व नरेन्द्र सिंह किरार सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मंचासीन थे।

स्व-सहायता समूहों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह ने कहा कि महिलायें आत्मनिर्भर बनेंगीं तभी हमारा प्रदेश व देश आत्मनिर्भर बनेगा। सरकार द्वारा इसी ध्येय के साथ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं को स्कूली बच्चों के गणवेश तैयार करने का काम सौंपा है। साथ ही गेहूँ उपार्जन व शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालन जैसे काम भी महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपे गए हैं। ग्वालियर जिले में भी कुछ महिला समूहों ने सफलतापूर्वक यह जिम्मेदारी निभाई है। श्री कुशवाह ने कहा सरकार की मंशा है कि महिलायें कर्ज माँगने वाली नहीं कर्ज देने वाली बनें। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए योजनायें बनाई हैं।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री किशोर कान्याल ने जानकारी दी कि जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 3236 महिला स्व-सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिनसे 36 हजार 945 परिवार जुड़े हैं। जिले में 306 ग्राम संगठन और 17 क्लस्टर लेवल फेडरेशन काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों का 50 करोड़ से ऊपर का टर्न ओवर हो चुका है। इसमें से 37 करोड़ रूपए की राशि समूहों ने बैंकों को वापस कर दी है। खुशी बात है कि जिले का एक भी महिला स्व-सहायता समूह डिफॉल्टर नहीं है। श्री कान्याल ने बताया कि महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फूलबाग स्थित ग्रामीण हाट बाजार में भी समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिये विशेष व्यवस्था की गई है।

धान, ज्वार एवं बाजरा की खरीदी के लिये 60 पंजीयन केन्द्र स्थापित

मुरैना। खरीफ मौसम विपणन वर्ष 2021-22 में धान, ज्वार एवं बाजरा खरीदी हेतु किसानों का पंजीयन करने के लिये जिले भर में 60 पंजीयन केन्द्र खोलने की अनुमति दी गई है। इस वर्ष 3 केन्द्र बढ़ाये गये है। पिछले वर्ष किसानों के पंजीयन के लिये जिले में 57 केन्द्र बनाये गये थे।

यह जानकारी हाल में आयोजित जिला उपार्जन समिति की बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी कलेक्टर श्री रोशन कुमार सिंह ने की। जिला आपूर्ति अधिकारी, उपसंचालक कृषि, उपायुक्त सहकारी संस्थायें, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपॉरेशन के जिला प्रबंधक, जिला विपणन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में बताया कि धान, ज्वार एवं बाजरा खरीदी के लिये किसानों के पंजीयन हेतु 60 पंजीयन केन्द्रों में अम्बाह में 8, पोरसा में 7, मुरैना में 15, जौरा में 10, कैलारस और सबलगढ़ में 3-3 केन्द्र खोले गये है।

बैठक में उपस्थित समिति में निर्णय लिया गया कि पिछली खरीदी के दौरान 3 सहकारी समिति जिनके विरूद्ध बाजरा उपार्जन में अनियमितायें की गई थी, जिनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज होने से एवं 10 पंजीयन केन्द्रों की सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें प्राप्त होने से इन 10 पंजीयन केन्द्रों को अपात्र घोषित किया गया।

बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 उपार्जन नीति 02 सितम्बर 2021 की कण्डिका 5(2) अनुसार विगत खरीफ विपणन वर्ष में उपार्जन एवं पंजीयन करने वाले एफ.पी.ओ. एवं महिला स्व-सहायता समूहों को पंजीयन हेतु पात्र किया गया है, किन्तु मुरैना जिले में विगत वर्ष में किसी भी एफ.पी.ओ. एवं महिला स्व-सहायता समूह द्वारा पंजीयन या उपार्जन कार्य नहीं किये जाने से उनके आवेदन पत्र अपात्र किये गये। इस वर्ष किसानों की सुविधा एवं कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के किसानों के पंजीयन हेतु 60 पंजीयन केन्द्र बनाये है।

खनिज संपदा की दृष्टि से मध्यप्रदेश खनिज बाहुल्य प्रदेश है – मंत्री श्री सिंह

भोपाल। खनिज साधन मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि खनिज संपदा की दृष्टि से मध्यप्रदेश एक खनिज बाहुल्य प्रदेश है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग सभी प्रकार के मुख्य एवं गौण खनिज पाये जाते हैं। वर्तमान में प्रदेश हीरा, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज, बाक्साइट, रॉक फास्फेट, लेटेराइट, डोलोमाइट आदि के उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है। केन्द्रीय खान मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश राज्य को जी-4 स्तर के 21 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध कराने के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में खनिज मंत्री श्री सिंह ने यह बात कही।

मंत्री श्री सिंह कहा कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को जी-4 श्रेणी के 100 ब्लॉक नीलामी के लिए प्रदाय किये जा रहे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा खनिज ब्लॉक मध्यप्रदेश राज्य को प्राप्त हुये हैं। उन्होंने कहा कि उक्त ब्लॉकों को नीलामी में रखे जाने की कार्यवाही तीव्र गति से होगी, जिससे भारत सरकार की मंशा अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में खनिज विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा मुख्य खनिजों के निवर्तन को नीलामी प्रक्रिया से देने का प्रवाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा अभी तक पाँच चरण नीलामी के फलस्वरूप 26 खनिज ब्लॉकों की एन.आई.टी जारी की गई है, जिसमें से 14 खनिज ब्लॉक आवंटित हो चुके हैं। इससे प्रदेश को खनिपट्टा अवधि में कुल 36739 करोड़ रूपये राजस्व के रूप में प्राप्त होना संभावित है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि आगामी चरणों की नीलामी के लिए 85 ब्लॉक चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से माह अक्टूबर 2021 में 20 ब्लॉक एवं मार्च 2022 तक 25 बलॉक की एन.आई.टी. जारी किया जाना प्रस्तावित है।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि खनिज विभाग द्वारा गौण खनिजों के 82 क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं, जिनमें नीलामी की प्रारंभिक प्रक्रिया प्रचलन में है। उन्होंने कहा कि राज्य के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का महत्वपूर्ण योगदान है। विगत वर्षान्त में प्रदेश का खनिज राजस्व 5185 करोड़ रूपये रहा है। मंत्री श्री सिंह ने भारत सरकार से आग्रह किया कि 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के खनिज ब्लॉकों को भी नीलामी में शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन किये जायें। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त ग्लोकोनाइट खनिज की सेल वेल्यू निर्धारित की जाये, जिससे प्रदेश के जिला सिंगरौली में उपलब्ध ग्लोकोनाइट खनिज ब्लॉक को नीलाम किया जा सकें। इससे प्रदेश के खनिज राजस्व में वृद्धि होगी।

खनिज साधन मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने विशेष रूप से सहयोग के लिए केन्द्रीय खान मंत्रालय का आभार व्यक्त किया।

महिला उद्यमशीलता पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल एवं दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल) द्वारा महिला उद्यमशीलता पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विश्वप्रकाश, आंचलिक निदेशक (मध्य) दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड भोपाल, कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल, विशिष्ट अतिथि डॉ. जी.बी. भालेराव, क्षेत्रीय निदेशक भोपाल एवं श्री संजय कुमार सिंह, राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी भोपाल की उपस्थिती मे किया गया। इस कार्यक्रम मे 18-40 वर्ष के 47 युवा-युवतियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुये श्री पृथ्वीराज सिन्हा, शिक्षा अधिकारी ने बताया कि म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल एवं दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल) के संयुक्त आयोजन मे यह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियो को नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संगठन - क्या, क्यों एवं कैसे की जानकारी श्री हरज्ञान सिंह अहिरवार, प्रशिक्षक द्वारा बताई है। केन्द्र / राज्य सरकार की असंगठित श्रमिकों हेतु विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजना पर श्री पृथ्वीराज सिन्हा शिक्षा अधिकारी दारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सहकारिता का अर्थ, विशेषताएं और महत्व (भूमिका), सहकारिता के सिद्धान्त, सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, महिला सहकारिता आंदोलन, केन्द्रीय सहायता, सहकारिता विभाग की योजना पर जानकारी श्री ए.के. जोशी, पूर्व प्राचार्य द्वारा प्रदान की गई। श्री संतोष येड़े, राज्य समन्वयक द्वारा महिला उद्यमिता की अवधारणा एवं क्षेत्र, भारत में महिला उद्यमिता की वर्तमान स्थिति, समस्याएँ एवं संभावनाओं का वर्णन, महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

श्रीमती मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर प्रशिक्षका द्वारा राज्य संघ द्वारा चलाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं अन्य योजना की जानकारी प्रदान की गई। केन्द्र एवं राज्य सरकार व विभिन्न एजेंसी द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओ पर श्री सुधीर मिश्रा, निदेशक ग्रामीण विकास एवं स्व - रोजगार प्रशिक्षण संस्थान भोपाल द्वारा प्रदान की गई। इस कार्यक्रम मे श्री जी.पी. मांझी, प्राचार्य, श्री विनोद कुशवाहा, श्री धनराज सैदान्ने , श्री प्रवीण कुशवाहा, श्री विक्रम मजूमदार का विशेष सहयोग रहा।

वनोपज सहकारी समितियों हेतु नेतृत्व विकास प्रशिक्षण आयोजित

भोपाल। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के संयुक्त आयोजन मे वनोपज सहकारी समितियों हेतु तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 06-09-2021 से 08-09-2021 तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में धार, अशोकनगर, विदिशा, रीवा, सीधी, दमोह, टीकमगढ़, शहडोल, सिवनी, देवास, सीहोर, श्योपुर, शिवपुरी, होशंगाबाद, रायसेन, सागर, छतरपुर, सतना, पन्ना जिलों के वनोपज सहकारी समितियों के 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुये श्री संजय कुमार सिंह, राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह प्रशिक्षण वनोपज सहकारी समिति के संचालको, सदस्यो के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमे विषय - विशेषज्ञो द्वारा महवपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। जैसे- सहकारी समिति के पदाधिकारी / प्रबंधकों के अधिकार, कर्तव्य एवं समिति का प्रबंधन पर श्री पी.के.एस. परिहार से.नि. प्रबंधक, अपेक्स बैंक द्वारा जानकारी प्रदान की गई। नेतृत्व विकास,

समय प्रबंधन, सम्प्रेषण कला,तनाव प्रबंधन विषय पर श्री अभय गोखले, पूर्व केडर अधिकारी, अपेक्स बैंक द्वारा जानकारी प्रदान की गई। समितियों का लेखांकन एवं वित्तीय पत्रकों का निर्माण पर श्री शशिकांत चतुर्वेदी, पूर्व प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। औषधीय पौधे, जड़ी - बूटियो का विनाश विहीन विदोहन पर तकनीकी जानकारी श्री सुधाकर पण्डागरे, विषय विशेषज्ञ सेडमैप द्वारा विस्तारपूर्वक दी गई। सहकारी अधिनियम की प्रमुख धाराए एवं सहकारी समिति के अंकेक्षण संबंधी विभिन्न प्रावधान पर श्री श्रीकुमार जोशी, से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया।

श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा अध्ययन भ्रमण दल को संतोष येड़े, राज्य समन्वयक के नेतृत्व में लघुवनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ. पी. पार्क, भोपाल के लिए हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया।

श्री सोनू सिंह मेहरा, प्रमाणीकरण अधिकारी, एम.एफ. पी. पार्क, भोपाल द्वारा औषधीय पौधो को पहचान कर उसके मार्केटिंग करने की योजना, औषधीय पौधे को सुखाने की प्रक्रिया तथा उनके प्रोसेसिंग की तकनीक, वन समितियों द्वारा उनके गांव के आस-पास के क्षेत्र में पैदा होने वाले औषधीय पौधे को वन समितियों के माध्यम से एकत्र कराये जाने की प्रक्रिया एवं उनको मिलने वाली मदद की जानकारी प्रदान की गई। डॉ. सुमन मिश्रा द्वारा लघुवनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल का भ्रमण कराया गया जिसमे औषधीय पौधे की पहचान, किस्म, प्रजाति, गुण एवं उनका उपयोग, केप्सूल, वटी, तेल, चूर्ण, आशव, शहद प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लेबलिंग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियो को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। इस कार्यक्रम का समन्वय श्रीमती रेखा पिप्पल, व्याख्याता के द्वारा किया गया। श्री जी.पी. मांझी, प्राचार्य, श्री ए.के.जोशी, पूर्व प्राचार्य श्री विनोद कुशवाहा, श्री धनराज सैदान्ने, श्री प्रवीण कुशवाहा, श्री विक्रम मजूमदार का विशेष सहयोग रहा।

क्रय हेतु "विभागीय कार्य मैन्युअल" उपलब्ध

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा निर्मित एवं प्रकाशित "विभागीय कार्य मैन्युअल" एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है तथा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश की मंशानुसार समस्त संभाग/जिलें तथा प्रदेश की समस्त प्रमुख, शीर्ष/जिला/प्राथमिक, सहकारी सोसायटियों में इसकी कम से कम एक प्रति संधारित की जावें। जिससे प्रकाशित मैन्युअल का लाभ विभागीय अधिकारी/कर्मचारी सहकारी संस्थाओं एवं उनके सदस्यों को हो सकें।

विभागीय कार्य मैन्युअल प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल से सम्पर्क करें। संपर्क सूत्र- 0755-2926160, 2926159, 9755270427 एवं आपके जिले में संचालित जिला सहकारी संघ से सम्पर्क कर सकते है।

हमारा उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में व्यवसाय और
जनशक्ति विकास में मान्यता प्राप्त नेतृत्व प्रदान करना है

MP STATE COOPERATIVE UNION LTD.
E-8/77, SHAHPURA, TRILANGA ROAD BHOPAL - 462039
Email: - rajyasanghbpl@gmail.com
Website: WWW.mpscu.in, Tel.:- 0755-2926160

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR EMPANELMENT OF MANPOWER OUTSOURCING AGENCY

Expression of Interest (EOI) is invited for empanelment of Manpower Out Sourcing Agency. The detailed terms and conditions of the EOI are given on our website www.mpscu.in. Interested parties may download EOI document from website.
The interested agencies may apply as per the directives mentioned in the EOI document on or before 20.09.2021 By 5 P.M. in the office of under signed. The Managing Director reserves the right to cancel this EOI without assigning any reason.

Managing Director

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।